There are 3250 towns in the country and out of them we have received information about something like 1826 town. How can I say a time limit?

THE DEPUTY CHAIRMAN; It depends upon the information which they receive from the State Governments. How can he say that? Later on, we will take all those towns.

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह : उपसभापति, महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर से ही यह निहित है कि बड़ा समय इसमें लिया जायेगा । अब हम इससे नाराज नहीं हैं कि मध्य प्रदेश के सात जिले हैं, आप मध्यप्रदेश के 20 ले लीजिए, मेरा यह निवेदन है मंत्री जी से। मगर हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ समस्यायें हैं शहरों की, कलकत्ता को एक समस्या है, बंबई को एक समस्या है, मद्रास की तीसरी समस्या है। तो आपने यह फरमाया कि टेस्टिंग हम बाद में शुरू करेंगे, जब राज्य सरकारों की रिपोर्ट आ जायेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या आप इस पर विचार करेंगे, सबसिक्वेंट इनेंहसमेंट जो आपने अपने उत्तर "डी" में लिखा है, इसके साथ ही क्यों नहीं मुख्तलिफ शहरों की आप टेस्टिंग करा लेते हैं, जिससे कि समय भी बचेगा ?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं कि हम किसी टाऊन को छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा--3250 टाऊन कण्ट्री में हैं, उसकी हमको रिपोर्ट आनी है और मैं माननीय सदस्य को यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह सबसे पहला कम्प्यूटराइज्ड पायलेट प्रोजैक्ट हमारा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारा अक्तूबर में भोपाल में आता है।

It *is* no problem.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 164, Shri Gurupadaswamy Absent. Dr. Bapu Kaldate. Absent Question No. 165. Dr. Vijayamohan Reddy. Absent.

*164. *[The questions (Shri M. S. Gurupadaswamy and Dr. Bapu Kaldate were absent. For answer* vide col. 35 infra].

♦165. *[The Questioner (Dr. G. Vajayamohan Reddy) was absent for answer,* vide *Col* 36-37 infra].

Urban Development in Madhya Pradesh

•166. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether the Central Government allocate funds for urban development in the States

(b) if so, the financial assistance provided to Madhya Pradesh during the years 1985-86 and 1986-87 in this regard; and

(c) the places where such funds have been utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) An outlay of Rs. 1,640 lakhs and Rs. 1,850 lakhs had been provided for urban development in the annual plans of Madhya Pradesh during the years 1985-86 and 1986-87, respectively. Loan assistance was given to the State Government for the Integrate Development of Small & Medium Towns, as per statement laid on the Table of the House. [See Appendix CXLin. Annexure No. 59] Further, under the centrally sponsored scheme of Urban Basic Services, an amount of Rs. 2.76 lakhs has been released as grant-in-aid for the development of Indore, Mhow and Depalpur towns in Indore district. Funds to thes

extent of $ 24.10 million have been made available under the Madhya Pradesh Urban Development Project, through the **World Bank over** the period 1983-89. The World Bank Project will cover Indore, Ujjain, Dewas, Raipur, Bhilai, Durg, Sagar, Shahdol, Ratlam and Khandwah.

श्रीमती रत्न कुमारी : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या जो केन्द्रीय सहायता प्रादेशिक सरकार को विकास के लिए दी गई है, वह सर्वेक्षण के बाद दी गयी है या सर्वेक्षण प्रदेश सरकार ने करवाया ?

श्री दलबीर सिंह : ये सारी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट्स से ही आती हैं। उनकी क्या प्रायमिकताएं हैं और कौन-कौन से शहरों को वे पहले प्रायमिकता देते हैं उस संबंध में उनके प्रपोजल्स और रिकमन-डेशंस आती हैं, उसी के आधार पर हम कार्यवाही करते हैं। मननीय सदस्या ने यह भी पूछा है कि मध्यप्रदेश को कितना पैसा मिला तो मैं बताना चाहूंगा कि 1979 से हम ने 680.27 लाख दिया है और यह बहुत ज्यादा है साथ ही हमारी वर्ल्ड बैंक की जो और योजनाएं हैं उनमें अभी 10 टाउंस को ले रहे हैं।

श्रीमती रत्न कुमारी : मंत्री महोदय, मैंने आपका स्टेटमेंट देखी है। बहुत से शहरों का नाम उसमें है, परंतु जबलपुर की उपेक्षा की गयी है जब कि वह एक असरदार शहर है मध्यप्रदेश का और वहां सुरक्षा संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है। हमारे विनोबा भावे ने इसे संस्थान धनी नाम दिया था। मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी जबलपुर का नाम इसमें जरूर जुड़वा देंगे।

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि जबलपुर के साथ कुछ भेद-भाव रखा गया है, ऐसा नहीं है। उसको हम ने वर्ल्ड प्रोजैक्ट में वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन में रखा है और उसमें हम कार्य-वाही करेंगे।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति महोदया, मध्यप्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य प्रांत है। जो सूची उत्तर में दी गयी है, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिन छोटे और मध्यम नगरों में मध्यप्रदेश में सहायता दी जा रही है उनमें से कोई भी आदिवासी बाहुल्य नगर नहीं है। बहुत से ऐसे जिला मुख्यालय हैं–मंडला, धार, झाबुआ, जगदलपुर ये सब आदिवासी बाहुल्य जिलों के मुख्यालय हैं और ये सुखद संयोग ही है कि माननीय मंत्री महोदय स्वतः आदिवासी हैं और मध्यप्रदेश के हैं। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या ऐसे जिलों को ऐसे नगरों को भी हम लेने का विचार कर रहे हैं दूसरी बात जो इसी से संलगन है, जो सूची दी गयी है, उसमें जिन गांवों को छठवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता दी गयी है उनको सातवीं में आह मदद नहीं दे रहे हैं जबकि उतकी मदद जारी रहने की आवश्य-कता है। तो क्या वह मदद आप जारी रखेंगे ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट्स को इगनोर किया गया है, यह सही नहीं है। मध्यम और छोटे शहर जो एक लाख से कम आबादी वाले हैं, उनमें मध्य प्रदेश से 16 लिए गए हैं जिनमें आदिवासी डिस्ट्री-क्टस जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैढन सीधी और अमरकंटक हैं। तो ऐसा नहीं है, कि ट्रायबल एरियाज को इगनोर किया गया है। छठवी पंचवर्षीय योजना में 235 शहर लिए थे और सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश से 102 टाउंस लिए गए हैं। इनमें 50 प्रतिशत खर्च स्टेट गवर्नमेंट और 50 प्रतिशत सैंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इगनोर कर रहे हैं।

श्री अजीत जोगी : जगदलपुर, झाबुआ जिला मुख्यालय हैं जो एक लाख से कम आबादी के शहर हैं ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय उप-सभापति महोदया, हमारे पास पैसा सी-मित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम को 88 करोड़ मिला और हम ने प्लानिंग कमीशन को फिर से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें और पैसा दो और अगर पैसा मिल जाता है तो उनको भी हम जोड़ेंगे।

श्री राधा किशन मालवीय : उपसभापति महोदया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इंदौर के लिए 2.76 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, रायपुर बिलासपुर, जबलपुर और ग्वालियर—ये बहुत बड़े-बड़े नगर हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन शहरों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार से कितने रुपए की सहायता की मांग कि और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इन शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि दी ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह तो स्टेट लोन है और उसके लिए सैंटर से कोई सैंट्रल असिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो 10 शहर हैं उनमें इंदौर की बात भी आई है। 24.10 अमेरिकन मिलियन डालर की जो बात है उसमें यह शहर भी कवर होते हैं। टेक्नीकली कुछ उसमें खामियां थीं जिसके लिए हमने स्टेट गवर्नमैंट को लिखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जो बेसिक नीड्स हैं वे इससे पूरी हो सक।

167. *[The questioner* (Shri D. B. Chandra Gowda) *was* absent. For answer, vide Col. 38-40 infra].

•168. *[The questioners (Shri* Lal K. Advani *and Shri Ashwani Kumar) were* absent. For answer, vide Col 40 infra]

Prompt Rehabilitation of Tribals

169. SHRI B. L. PANWAR t SHRI KAPIL VERMA; Will the Minister of WELFARE he pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued to the States to ensure prompt rehabilitation of tribals uprooted due to implementation of development projects in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is Government's view about widespread complaints that the funds sanctioned under various schemes are not reaching the bene ficiaries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJ-PAI): (a) and (b) Yes, Madam. The existing guidelines were issued in Feb. 86. Bureau of Public Enterprises in respect of land acquisition and rehabilitation aspects involved in major projects which apply to tribals also. Under these guidelines, rehabilitation will be monitored by Rehabilitation Cells to be set up by Project Authorities. The entire cost of rehabilitation will form a part of the project cost. Where the oustees are tribals, the guidelines further provide that the Ministry of Welfare and Ministry of Environment and Forests would be associated with the prepartion of the rehabilitation shcemes. On acquisition of land, these guidelines guard against indiscriminate acquisition in excess of actual requirements.

(c) Although Government has not received specific complaints regarding sanctioned funds not reaching the displaced tribals, the guidelines are under review to provide for adequate and effective rehabilitation and resettlement of tribals ouested by major projects.

श्री भंवर लाल पंवार : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में एक शब्द का प्रयोग किया है "विशिष्ट" और कहा है कि पुर्नवास के लिए स्वीकृत धनराशि विस्थापितों तक नहीं पहुंचने के संबंध में विशिष्ट शिकाय तें प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन यह वास्तविकता है और सत्य है और एक वकील के नाते मेरे पास फिगर्स भी हैं कि कहां-कहां हिन्दुस्तान में बांध की योजनाएं बनी हैं

The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. L. Panwar.